बहुजन हिताय! बहुजन सुखाय!

# सक्षम भारत

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक | इन्द्रजीत सिंह, मुख्य संवाददाता/सचिव, CNSI-Delhi

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रसारित

www.sakshambharat;net, E-mail : saksham.bharat@hotmail.com

Member : CENTRAL NEWSPAPER SOCIETY OF INDIA DELHI

● वर्ष: 23 ● अंक: 194 ● नई दिल्ली ● शनिवार 02 अगस्त 2025 ● प्रभात कालीन ● मूल्य: 3 रूपया ● पृष्ठ: 8

रिपब्लिकन मजदूर संगठन के सदस्य बनें

E-mail : rmsdp@hotmail.com

अनागरिक गीता भारती भवन
बी-2/370, सुल्तानपुरी
दिल्ली-86

### सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले पर लगाई रोक, कहा- कंजुरमार्ग संरक्षित वन भूमि नहीं

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बॉम्बे उच्च न्यायालय के उस फैसले पर रोक लगा दी, जिसमें मुंबई में कंजुरमार्ग इलाके की 120 हेक्टेयर जमीन को संरक्षित वन घोषित किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब ग्रेटर मुंबई नगर पालिका का कंजुरमार्ग इलाके में कचरा डालने का रास्ता साफ हो गया है। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की पीठ के समक्ष महाराष्ट्र सरकार की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि इस इलाके का इस्तेमाल पहले भी कचरा डालने के लिए होता था और यह जगह गलती से संरक्षित वन घोषित हो गई थी। बाद में सरकार ने इसे डी-नोटिफाई कर दिया था। हालांकि उच्च न्यायालय ने इसे मानने से इनकार कर दिया।

## मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुरू की दिल्ली को कूड़े से आजादी अभियान, हाथ में ली झाड़ू और कर डाला सरकारी दफ्तर को साफ

नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली को कूड़े से आज़ादी अभियान की शुरुआत करते हुए, दिल्ली के आईएसबीटी कश्मीरी गेट स्थित महिला एवं बाल विकास (डब्ल्यूसीडी) कार्यालय में स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया और कचरे के ढेर साफ़ किए। पत्रकारों से बात करते हुए, दिल्ली की मुख्यमंत्री ने दिल्ली में व्यवस्था सुधारने का दावा करने, लेकिन ऐसा न करने पर पिछली आप सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि मुझे इतना दर्द हो रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये वो कार्यालय हैं जो दिल्ली की व्यवस्था सुधारने का दावा करते हैं। पिछली सरकारों की हालत देखते हुए, इन परिस्थितियों में, हमारे अधिकारी किसी का भला कैसे कर सकते हैं... पानी टपक रहा है। रेखा गुप्ता ने आगे कहा कि इस इमारत में 2021 में आग लग गई, जबकि इस इमारत की न तो मरम्मत हुई थी और न ही इसकी सफ़ाई। क्या इन अधिकारियों को यहाँ अपनी जान गँवाने के लिए रखा गया है? महिला एवं बाल विकास विभाग कार्यालय का अपना पहला दौरा बताते हुए उन्होंने कहा, मैं पहली बार यहाँ आई हूँ, लेकिन ऐसी महत्वपूर्ण समितियों/विभागों की दयनीय स्थिति देखकर बहुत दुःख हुआ, जहाँ कागज़ात रखने के लिए न अलमारी है,



न कुर्सी, और पता नहीं कब पंखा ऊपर से गिर जाए। सफ़ाई के आदेश एक ऐसी चीज़ है जो हम कर सकते हैं। अगर सब लोग इसमें शामिल हों तो ये पूरे हो जाएँगे। हालाँकि, अपने अधिकारियों को ऐसी खराब परिस्थितियों में काम करते देखना मेरे लिए वाकई बहुत दुखद है। उन्होंने पिछली आप सरकार पर अपने शीश महल बनाने के लिए 70 करोड़ रुपये खर्च करने और कार्यालयों के सुधार पर कोई पैसा खर्च न करने का आरोप लगाया। गुप्ता ने कहा, उन्हें (आप) कार्यालयों की मरम्मत के लिए निवेश करने का समय नहीं मिला, लेकिन अपने लिए शीश महल बनाने के लिए 70 करोड़ रुपये थे। अगर उन्होंने यहाँ 2-4 करोड़ रुपये का निवेश किया होता, तो कम से कम कुछ कार्यालय तो अच्छा प्रदर्शन कर पाते। दिल्ली की मुख्यमंत्री ने यह भी दावा किया कि वह सभी विभागों के लिए नए कार्यालयों का निर्माण सुनिश्चित करेंगी, एक अनुकूल कार्य वातावरण तैयार करेंगी और प्रभावी कार्य के लिए उन्हें पर्याप्त कार्यस्थल प्रदान करेंगी। उन्होंने आगे कहा, दिल्ली का एक बिल्कुल नया सेक्टर बनाया जाना चाहिए जहाँ हर विभाग को जगह मिले। हम आज ही इस प्रक्रिया की शुरुआत करेंगे। हम दिल्ली के अपने नए सेक्टर के लिए एक जगह ढूँढ़ेंगे...जहाँ हमारे सभी विभाग स्थित हो सकें। मौजूदा खराब हालात के बावजूद, हम अपने अधिकारियों को नहीं बख्शेंगे और उनकी मदद करेंगे।

## दिल्ली की झुग्गियों में रहने वाले लोगों के लिए खुशखबरी, सीएम रेखा गुप्ता ने किया ये ऐलान



नई दिल्ली। दिल्ली में कई झुग्गी बस्तियों पर बुलडोजर चलने के आरोपों के बीच मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बड़ा ऐलान किया है. उन्होंने शुक्रवार (1 अगस्त) को कहा कि जब तक झुग्गीवासियों को स्थायी आवास नहीं दिया जाता, तब तक शहर में कोई भी झुग्गी नहीं तोड़ी जाएगी. हर एक को मकान देंगे, और एक भी झुग्गी टूटने नहीं देंगे. न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, रेखा गुप्ता ने कहा कि यदि आवश्यकता पड़ी, तो उनकी सरकार सभी को सम्मानजनक आवास सुनिश्चित करने के लिए नीतियों में संशोधन भी करेगी. सीएम ने ये वादा ऐसे समय में किया है जब विपक्षी आम आदमी पार्टी (आप) लगातार बीजेपी को घेर रही है. उसका दावा है कि कई झुग्गियों पर बुलडोजर चलाया गया और कईयों पर चलाने की तैयारी है और इसके बदले घर भी नहीं दिए गए हैं.

पिछले दिनों दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा था, मद्रासी कैंप, भूमिहीन कैंप, वजीरपुर, जेलरवाला बाग, गोकुलपुर, मादीपुर में बुलडोजर चला. अब शालीमार बाग और रेहतास नगर में बुलडोजर चलाने की तैयारी शुरू हो गई है. एनसीटी में सतत विकास विषय पर आयोजित सेमिनार ग्रोथ भी, ग्रीन भी के दौरान कहा कि अब दिल्ली को बेहतर स्कूल, अस्पताल, सड़कें, जल और सीवर लाइनें, सौर ऊर्जा एवं वर्षा जल संचयन प्रणाली और एक पुनर्जीवित यमुना के साथ विकास की गति तेज करनी होगी. मुख्यमंत्री गुप्ता ने कहा, प्रधानमंत्री ने कहा है दिल्ली आगे बढ़ेगी तो देश आगे बढ़ेगा.रेखा गुप्ता ने आगे कहा कि उनके सभी मंत्री प्रतिदिन 16 से 18 घंटे काम कर रहे हैं ताकि दिल्ली उन राज्यों और शहरों की गति पकड़ सके जो राष्ट्रीय राजधानी से आगे निकल गए हैं. उन्होंने कहा, दिल्ली की जनता ने पिछले 27 वर्षों में बहुत कुछ खोया है. अब हमें शून्य से फिर से शुरुआत करनी है. रेखा गुप्ता ने 1954 के श्रम कानूनों की भी आलोचना की. इसके नियम महिलाओं को नाइट शिफ्ट में काम करने से रोकता था. उन्होंने कहा, रात में काम करना या न करना यह महिला का निर्णय होना चाहिए. सरकार उन पर कोई निर्णय थोप नहीं सकती. उन्होंने घोषणा की कि दिल्ली सरकार ने यह प्रतिबंध हटा दिया है, जिससे महिलाओं को अधिक अवसर मिलेंगे और साथ ही सुरक्षित कार्य वातावरण भी सुनिश्चित किया जाएगा. रेखा गुप्ता ने कहा, दिल्ली भारत की राजधानी है और यह तेज विकास, बेहतर बुनियादी ढांचे, तकनीक और अपने निवासियों के लिए बेहतर जीवन की हकदार है. अब हमारे पास फिर से निर्माण करने और चीजों को सही करने का अवसर है.

## राज्यसभा वेल में सीआईएसएफ जवानों का आना बेहद आपत्तिजनक; खरगे ने उपसभापति को लिखा पत्र

नई दिल्ली।

वरिष्ठ कांग्रेस सांसद और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने उपसभापति हरिवंश को पत्र लिखा है। उन्होंने सदन के वेल में सीआईएसएफ जवानों के आने की घटना को बेहद आपत्तिजनक बताया और कहा कि संसद में ऐसी घटना हैरान करने वाली है। खरगे ने उपसभापति को लिखे पत्र में कहा, भविष्य में, जब राज्यसभा सदस्य जनहित के महत्वपूर्ण मुद्दे उठा रहे होंगे, तो सीआईएसएफ कर्मी सदन के वेल में नहीं आएंगे, उन्हें ऐसी उम्मीद है। बता दें कि संसदीय नियमावली के तहत सदन की कार्यवाही चलते समय सदन के वेल में सांसदों का आना प्रतिबंधित होता है। इसे सदन में अव्यवस्था के साथ-साथ सभापति के आसन पर दबाव बनाने के प्रयास की तरह देखा जाता है। सदन के वेल में घुसने को लेकर सभापति सांसदों को आगाह करते हैं। पीठासीन सभापति के निर्देशों और अपील का उल्लंघन करने पर सांसदों को निलंबित भी किया जा सकता है। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने उपसभापति डॉ हरिवंश को लिखे पत्र में कहा, हम इस बात से हैरान और स्तब्ध हैं कि सीआईएसएफ कर्मियों को सदन के वेल में प्रवेश की अनुमति दी जा रही है। उन्होंने कहा कि जिस समय राज्यसभा सदस्य जब अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं... उस समय सुरक्षाकर्मियों का सदन के वेल में आना बेहद आपत्तिजनक है और वे इसकी कड़ी निंदा करते हैं। खरगे ने लिखा, हम उम्मीद करते हैं कि भविष्य में, जब सदस्य जनहित के महत्वपूर्ण मुद्दे उठा रहे होंगे, तो सीआईएसएफ कर्मी सदन के वेल में नहीं आएंगे। संसद की कार्यवाही संचालन के समय सभापति



के आसन के ठीक सामने राज्यसभा महासचिव बैठते हैं। उनके अलावा सदन की कार्यवाही चलाने में मदद करने वाले कई अन्य पदाधिकारी भी होते हैं। सांसदों के बैठने की जगह और सभापति के आसन के बीच अर्धचंद्राकार या यू शेप वाले हिस्से को सदन का वेल कहा जाता है। इस जगह पर बिना अनुमति के आना नियमों का उल्लंघन और अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है। सदन के वेल में आना इसलिए भी आपत्तिजनक है क्योंकि राज्यसभा महासचिव और उनके अन्य सहयोगी पदाधिकारियों के पास संवेदनशील और आधिकारिक संसदीय दस्तावेज होते हैं। बीते कुछ समय में इस जगह पर आने के कारण कई सांसदों को निलंबन का दंड भी झेलना पड़ा है। हंगामा और शोरशराबा करने के बाद उग्र हुए कुछ सांसदों ने तो मर्यादा की तमाम सीमाओं को तोड़ते हुए महासचिव की टेबल पर चढ़ने से भी गुरेज नहीं किया। ऐसे अशोभनीय आचरण करने वाले सांसदों को पूर्व उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के तत्कालीन सभापति वेंकैया नायडू ने सदन से पूरे सत्र निलंबित कर दिया था।

## कांग्रेस ने सेना, संत, सनातन और संविधान पर 17 वर्षों तक किया हमला, कोर्ट के फैसले पर बोले संबित पात्रा

नई दिल्ली। भाजपा ने शुक्रवार को कहा कि कांग्रेस पार्टी पिछले 17 सालों से वोट बैंक की राजनीति के लिए हिंदुओं को बदनाम करने की एक सोची-समझी रणनीति के तहत संतों, सैनिकों, सनातन धर्म और संविधान पर हमला करती रही है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने यहां पार्टी मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि कांग्रेस ने 17 सालों तक संतों, सैनिकों, सनातन धर्म और संविधान - इन चारों पर हमला किया। यह वोट बैंक की राजनीति के लिए हिंदुओं को बदनाम करने की एक सोची-समझी रणनीति थी। लेकिन अंत में, सत्य की जीत हुई। संबित पात्रा ने कहा कि जिस प्रकार से देश में भगवा आतंकवाद के नैरेटिव को फैलाने की कोशिश कांग्रेस की सरकार ने की थी और जिस प्रकार गांधी परिवार की चेष्टा थी कि हिंदुओ को अपमानित किया जाए! कहीं न कहीं तुष्टिकरण की राजनीति और वोटबैंक की राजनीति के कारण गांधी परिवार की ये तीव्र इच्छा थी कि सनातन एवं हिंदुओ पर कुठाराघात किया जाए।कल मालेगांव पर कोर्ट का जो फैसला आया है, उससे ये नैरेटिव औंधे मुंह गिर गया है। पात्रा ने कहा कि लेकिन आज उसमें 2 नए खुलासे हुए हैं। मालेगांव ब्लास्ट के दौरान जो ATS थी, जिसने जांच की थी, उसके एक अधिकारी महबूब मुजावर का एक खुलासा हुआ है, ये खुलासा बहुत ही चौंकाने वाला है।

आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में महबूब मुजावर के इस खुलासे पर बातचीत होगी और दूसरा राहुल गांधी के कहने पर पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के कद्दावर नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने जिस प्रकार का बयान दिया है, उस पर इस प्रेस कांफ्रेंस में चर्चा होगी। भाजपा नेता ने कहा कि महबूब मुजावर ने आज सुबह खुलासा किया है कि उनके जो उच्चाधिकारी थे और सरकार के बड़े लोगों ने महबूब जी और ATS के ऊपर बहुत यादा प्रेशर डाला था कि किसी भी कीमत पर इस भगवा आतंकवाद नैरेटिव को और आगे बढ़ाने के लिए RSS के आदरणीय सर संघचालक मोहन भागवत जी को गिरफ्तार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि चार्जशीट में नाम नहीं, जांच में कहीं भी कोई नाम नहीं था, फिर भी जब गिरफ्तारी का आदेश दिया गया, तो महबूब मुजावर ने संविधान का हवाला देते हुए कहा कि मैं ये काम नहीं कर सकता, क्योंकि ये संविधान सम्मत नहीं है। बदले में बड़े अधिकारियों ने महबूब मुजावर जी पर कुछ इल्जाम लगाए, जिसके कारण उनकी पदोन्नति भी रुक गई। बाद में महबूब मुजावर कोर्ट गए और कोर्ट ने उन्हें छोड़ते हुए कहा कि ये निर्दोष हैं और उनके खिलाफ जो आरोप लगाए गए हैं, वो गलत है। पात्रा ने कहा कि आप उस समय की कांग्रेस सरकार के प्रतिशोधात्मक रवैये को देखिए कि जबरन किस प्रकार से भाजपा और जो लोग हिंदू धर्म को मानते हैं, और संघ के उच्च पदों पर आसीन हैं, किस प्रकार से उनको अपमानित और गिरफ्तार किया जाए। इस प्रकार के प्रतिशोधी रवैया के साथ उस समय की कांग्रेस पार्टी काम कर ही थी और ये सब गांधी परिवार के कहने पर हो रहा था। पृथ्वीराज चव्हाण जी ने आज भी अपने बयान को दोहराया है। उन्होंने 2 बातें कही हैं - पहली बात कही गई है कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता, ये तुष्टिकरण का तकिया कलाम है। ये तमाम कांग्रेसी नेता तब कहते हैं, जब कोई आतंकवादी हमला होता है, ताकि वो आने वोटबैंक को साध सकें और तुष्टिकरण की राजनीति को साध सकें। फिर पृथ्वीराज चव्हाण जी कहते हैं कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता है, कहना ही है तो आप कहो कि हिंदू आतंकी या सनातन आतंकी!

## दिल्ली-एनसीआर में सुबह से रिमझिम, कई दिन बरसेंगे बदरा

नई दिल्ली । राजधानी पर मानसून मेहरबान बना हुआ है। बीते दो दिन से राजधानी में जमकर बदरा बरस रहे हैं। आज भी सुबह से दिल्ली-एनसीआर में बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने शुक्रवार के लिए हल्की वर्षा होने की संभावना जताई थी। ऐसे में अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 34 और 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। बुधवार को शुरू हुआ बारिश का सिलसिला आज भी जारी रहा। कल सुबह से ही झमाझम बारिश हुई। इस दौरान आसमान में काली घटा छाई रही। इसके चलते मौसम सुहावना बना रहा। झमाझम बरसात ने जहां दिल्ली-एनसीआर वालों को उमस से राहत दिलाई, तो वहीं ये आफत बनकर भी बरसी। कई इलाकों में जलभराव के साथ घंटों तक लगे जाम दिल्ली-एनसीआर वालों की भी रफ्तार धीमी कर दी। सुबह समय से स्कूल-कॉलेज और दफ्तर पहुंचने वालों की परेशानी बढ़ी। बारिश के चलते दिल्ली-एनसीआर में कई सड़कों पर लोगों को जाम का सामना करना पड़ा। ऐसे में सड़कों पर वाहन रेंगते नजर आए। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में बुधवार सुबह 8:30 बजे से गुरुवार सुबह 8:30 बजे तक सफदरजंग मानक वेधशाला में 39.1 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। वहीं, गुरुवार सुबह 5:30 बजे तक दिल्ली में 16.6 बारिश हुई।

पालम में 79, नजफगढ़ में 61, आया नगर में 51.1, रिज में 34.4, राजघाट में 9.8, लोधी रोड में 9.3 और पूसा में 9 मिमी बारिश दर्ज की गई। इस दौरान अधिकतम तापमान सामान्य से 4.5 डिग्री सेल्सियस कम के साथ 29.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं, न्यूनतम तापमान सामान्य से 2.4 डिग्री सेल्सियस कम के साथ 24.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बीते 24 घंटे में हवा में नमी का स्तर 100 से 98 फीसदी रहा।

# ट्रंप: हुए तुम दोस्त जिसके

**आखिर** अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25 फीसदी टैरिफ बम फोड़ दिया है। हालांकि उन्होंने भारत को अपना दोस्त बताते हुए बहुत ही कड़े शब्दों का इस्तेमाल करते हुए रूस से तेल, ऊर्जा और हथियार खरीदने पर भारत पर जुर्माना लगाने का भी ऐलान कर दिया है। अमेरिका एक ऐसा देश है जिसे स्वयं नहीं पता कि वह कहां जा रहा है, पर वह उस जगह पहुंचने पर स्पीड रिकार्ड बनाने को कृतसंकल्प है। डोनाल्ड ट्रंप पर महान बनने की सनक सवार है और इसी सनक में वह एक के बाद एक ऐसे कदम उठाते जा रहे हैं जिससे पूरी दुनिया में उथल-पुथल मचाए हुए है। बार-बार टैरिफ की धमकी के पीछे ट्रंप का एक ही मकसद है अमेरिकी उद्योगों को बढ़ावा देना और व्यापार घाटे को कम करना। भारत के साथ व्यापार वार्ता में प्रगति में गतिरोध से ट्रंप हताश है और उन्हें लगता है कि 25 फीसदी टैरिफ लगाने से भारत झुक जाएगा। ट्रंप ब्रिक्स देशों के समूह से भी काफी परेशान है। उन्हें डर है कि अमेरिकी डॉलर का विकल्प तलाशने की ब्रिक्स की पहल डॉलर को कमजोर बना देगी। ब्रिक्स में भारत भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ऐसा लगता है कि ट्रंप चीन और रूस के बाद भारत से भी भयभीत नजर आते हैं। भारत-अमेरिका संबंधों का अवलोकन किया जाए तो उसने हमेशा ही भारत विरोधी रुख अपनाया है। चाहे वो निक्सन का शासन काल हो, चाहे वो बुश का कार्यकाल हो, चाहे वो क्लिंटन का कार्यकाल हो कौन नहीं जानता कि अमेरिका ने पाकिस्तान पर हमेशा ही डॉलरों की बरसात की और उसे आतंकवाद को पालने का भरपूर मौका दिया। कौन नहीं जानता कि पाकिस्तान में आतंकवादी अमेरिका के पैसों से पलते रहे और ट्रेनिंग लेते रहे। भुखमरी और आर्थिक कंगाली के कगार पर पहुंचे पाकिस्तान को किसी ने जिन्दा रखा तो वह अमेरिका है। 16 मई 1974 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के शासनकाल में पोखरण में परमाणु परीक्षण किए तो अमेरिका आग-बबूला हो गया था। तब 1978 में अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने भारत को परमाणु सहायता निर्यात करना बंद कर दिया और कई तरह के आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए थे। 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में पोखरण परीक्षण-2 किया गया तब भी भारत पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए थे। यह प्रतिबंध तब तक बने रहे जब 2008 को अमेरिकी राष्ट्रपति जार्ज डब्ल्यू बुश और तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने पहली बार परमाणु समझौते में प्रवेश करने के अपने इरादे की घोषणा की। रूस ने हमेशा युद्ध काल हो या शांति काल भारत की मदद की। रूस से भारत की मैत्री हमेशा ही अमेरिका की आंखों में खटकती रही है। रूस ने भारत में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और साथ ही भारत की सेना को शक्तिशाली बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। भारत न कभी पहले अमेरिकी प्रतिबंधों से विचलित हुआ और न ही अब होगा। ट्रंप चाहते हैं कि भारत रूस के बदले अमेरिका से सैन्य उपकरण खरीदे और तेल को लेकर भी भारत रूस पर निर्भरता कम करे। भारत-रूस संबंध इतने प्रगाढ़ हैं क्योंकि युद्धों के दौरान जब अमेरिका पाकिस्तान के साथ खड़ा था तब रूस ने ही भारत को रक्षा संधि का कवच प्रदान किया। रूस न केवल हमें सैन्य उपकरण देता है, बल्कि उसकी तकनीक भी देता है।

जबकि अमेरिका हमें तकनीक नहीं देता। रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद अमेरिका ने भारत पर रूस से एस-400 सुरक्षा कवच और तेल नहीं लेने के लिए दबाव डाला लेकिन केन्द्र की नरेन्द्र मोदी सरकार ने अमेरिकी दबाव को दरकिनार कर भारतीय हितों की रक्षा करते हुए रूस से व्यापार जारी रखा। इस 'टैरिफ स्ट्राइक' का भारतीय अर्थव्यवस्था, विशेषकर स्मार्ट फोन, फार्मा, टेक्सटाइल, रत्न और आभूषण तथा ऑटो पार्ट्स जैसे प्रमुख निर्यात क्षेत्रों पर सीधा असर पड़ेगा। रुपए पर दबाव बढ़ने और शेयर बाजार में अस्थिरता की आशंका है। हालांकि भारत सरकार ने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने की बात कही है और अभी भी एक संतुलित व्यापार समझौते की उम्मीद कर रही है। अमेरिका द्वारा भारत पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाए जाने के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। यह देखना भी महत्वपूर्ण है कि भारत इस चुनौती से कैसे निपटता है और क्या ये व्यापक द्विपक्षीय संबंधों को प्रभावित करती है। अमेरिका में भारतीय उत्पाद महंगे होंगे। अमेरिका में आईटी सेवाएं देने वाली कम्पनियों पर कर का बोझ बढ़ेगा और शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिल रही है। आर्थिक विशेषज्ञों का कहना है कि भारत को व्यापार संतुलन बनाए रखने के लिए ग्लोबल इकोनमी पर संभावित नकारात्मक असर के लिए तैयार रहना होगा। कुछ आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि शुरू-शुरू में अमेरिकी टैरिफ का असर दिखाई देगा लेकिन भारत इस समय बड़ी आर्थिक शक्ति है। धीरे-धीरे इसका असर कम होता जाएगा। भारत के लिए यह चिंता का विषय है कि ट्रंप का झुकाव पाकिस्तान की तरफ बढ़ा है और अमेरिका फिर पाकिस्तान को गले लगा रहा है। भारत को अमेरिका के आगे झुकना स्वीकार्य नहीं होगा। ट्रंप और अमेरिका को लेकर भारत की आम जनता का मूड नकारात्मक हो रहा है। खासकर ऑपरेशन सिंदूर के बाद मोदी सरकार जनमानस की भावनाओं के खिलाफ नहीं जा सकती। भारत का स्वाभिमान हमेशा जिंदा रहा है और आगे भी रहेगा। भारत सरकार ने स्पष्ट कर दिया है। सरकार का कहना है कि वह अपने किसानों, उद्यमियों और छोटे मध्यम उद्योगों के हितों की रक्षा के लिए हर कदम उठाएगी और राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देगी। फिलहाल अमेरिका से व्यापार वार्ता जारी है और सरकार विभिन्न विकल्पों पर विचार कर रही है। इतना तय है कि अमेरिका जैसा तथाकथित दोस्त रूस की जगह नहीं ले सकता।

# धनखड़ का धमाल

**यह** दूसरी बार है जब निवर्तमान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने विपक्ष की मांग मानी है। शायद कुछ महीनों की देरी से लेकिन अंततः उन्होंने वही किया जिसकी मांग विपक्षी सांसद पिछले साल से कर रहे थे। पिछले साल दिसंबर में 'इंडिया गठबंधन' के 60 सांसदों ने धनखड़ को हटाने की मांग की थी। उन्होंने एक प्रस्ताव का नोटिस सौंपा था, जिसमें कहा गया था कि धनखड़ ने 'स्पष्ट रूप से पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया है और विपक्षी सदस्यों के प्रति अनुचित व्यवहार किया है।' स्वाभाविक रूप से यह नोटिस राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश द्वारा खारिज कर दिया गया। उनका तर्क था कि यह प्रस्ताव जल्दबाजी में लाया गया था और इसका उद्देश्य उपराष्ट्रपति की छवि खराब करना था। कुछ महीनों बाद, वही विपक्ष जो कभी उनके इस्तीफे की मांग कर रहा था, अब उनके समर्थन में खड़ा है। और धनखड़ जो पहले अपने पद पर अड़े हुए थे, अब वही कर गए जिसकी उम्मीद विपक्ष उनसे पिछले साल कर रहा था। उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। धनखड़ ने अपने इस्तीफे का कारण स्वास्थ्य बताया है। जिस गति से उन्होंने इस्तीफा दिया उसने सभी को चौंका दिया है। वही विपक्ष जो पहले उनके खिलाफ मोर्चा खोले हुए था, अब उन्हें किसान पुत्र कहकर उनकी प्रशंसा कर रहा है। इस पूरे घटनाक्रम में आया पलटा वह बेहद दिलचस्प है। कांग्रेस के जयराम रमेश ने कहा कि धनखड़ को 'राष्ट्र हित' में अपना इस्तीफा वापस लेना चाहिए। यह वही रमेश हैं जिन्होंने पहले आरोप लगाया था कि धनखड़ 'सरकार के प्रचारक की तरह' व्यवहार करते हैं, न कि एक निष्पक्ष मध्यस्थ की तरह। वे विपक्ष द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव का नेतृत्व करने वालों में भी शामिल थे लेकिन अब रमेश उनकी निर्भीकता की सराहना कर रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी धनखड़ के समर्थन में बयान दिया है। यह वही खड़गे हैं जो कई बार उन पर संसद में बोलने से रोकने का आरोप लगाते रहे हैं।

धनखड़ और विपक्ष के बीच जो आज समीकरण दिखाई दे रहे हैं, वह हाल ही में बने हैं। इस्तीफे से पहले तक उनका विपक्ष के साथ टकराव का रिश्ता रहा है। तृणमूल सांसद कल्याण बनर्जी ने उन्हें मंच से नकल उतारकर निशाना बनाया था, साथ ही उनके महंगे सूट पर भी टिप्पणी की थी कि वह 'लाखों का सूट पहनते हैं।' सपा सांसद जया बच्चन की धनखड़ से बहस तब हुई जब उन्होंने सदन में उनकी आवाज के 'अस्वीकार्य लहजे' को लेकर आपत्ति जताई थी। उन्होंने करीब एक साल पहले सदन में गरजते हुए कहा था, 'मुझे माफी चाहिए।' इसके अलावा उनका यह भी आरोप था कि जब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोलने के लिए खड़े हुए तब उपराष्ट्रपति ने उनका माइक बंद करवा दिया। अब तस्वीर बदल चुकी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के महाभियोग प्रस्ताव के संदर्भ में विपक्ष का समर्थन करने के कारण धनखड़ को पद छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। गौरतलब है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश यशवंत वर्मा के आधिकारिक आवास से बड़ी मात्रा में नकदी बरामद होने के बाद उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं।

उपराष्ट्रपति के रूप में जगदीप धनखड़ राज्यसभा के पदेन सभापति भी थे। यह दूसरी बार है जब निवर्तमान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने विपक्ष की मांग पर सहमति जताई है। हालांकि इसमें कुछ महीनों की देरी जरूर हुई लेकिन अंततः उन्होंने वह कदम उठाया जिसकी मांग विपक्षी सांसद लगातार कर रहे थे। दिसंबर 2023 में 'इंडिया गठबंधन' के 60 सांसदों ने उपराष्ट्रपति धनखड़ को उनके पद से हटाने की मांग करते हुए एक प्रस्ताव का नोटिस दिया था। विपक्ष का आरोप था कि धनखड़ ने 'खुले तौर पर पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया है और विपक्षी सांसदों के प्रति भेदभावपूर्ण व्यवहार किया है।' राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने यह नोटिस खारिज कर दिया था। उनका कहना था कि यह प्रस्ताव जल्दबाजी में लाया गया है और उपराष्ट्रपति की छवि को धूमिल करने का प्रयास है। जगदीप धनखड़ ने अगस्त 2022 में उपराष्ट्रपति पद का कार्यभार संभाला था। उन्होंने तय समय से दो साल पहले ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उनका कार्यकाल वर्ष 2027 में समाप्त होना था। धनखड़ और विपक्ष के बीच जो आज समीकरण दिखाई दे रहे हैं, वह हाल ही में बने हैं। इस्तीफे से पहले तक उनका विपक्ष के साथ टकराव का रिश्ता रहा है। तृणमूल सांसद कल्याण बनर्जी ने उन्हें मंच से नकल उतारकर निशाना बनाया था, साथ ही उनके महंगे सूट पर भी टिप्पणी की थी कि वह 'लाखों का सूट पहनते हैं।' सपा सांसद जया बच्चन की धनखड़ से बहस तब हुई जब उन्होंने सदन में उनकी आवाज के 'अस्वीकार्य लहजे' को लेकर आपत्ति जताई थी।

उन्होंने करीब एक साल पहले सदन में गरजते हुए कहा था, 'मुझे माफी चाहिए।' इसके अलावा उनका यह भी आरोप था कि जब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोलने के लिए खड़े हुए तब उपराष्ट्रपति ने उनका माइक बंद करवा दिया। अब तस्वीर बदल चुकी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के महाभियोग प्रस्ताव के संदर्भ में विपक्ष का समर्थन करने के कारण धनखड़ को पद छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। गौरतलब है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश यशवंत वर्मा के आधिकारिक आवास से बड़ी मात्रा में नकदी बरामद होने के बाद उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। सरकार ने लोकसभा में उनके खिलाफ महाभियोग प्रक्रिया की शुरुआत की थी और 153 सांसदों ने प्रस्ताव के पक्ष में हस्ताक्षर किए थे। इसी तरह राज्यसभा में 63 सांसदों ने उपराष्ट्रपति को नोटिस भेजा। ध्यान देने वाली बात यह है कि राज्यसभा के सभी हस्ताक्षरकर्ता विपक्षी दलों से थे। तो सवाल उठता है कि राज्यसभा के भाजपा सांसद इस प्रक्रिया से बाहर क्यों रहे? जवाब स्पष्ट है उन्हें राज्यसभा में दिए गए नोटिस की जानकारी ही नहीं थी। यह घटनाक्रम न केवल सरकार की लोकसभा में चलाई जा रही कार्रवाई को बाधित करता है, बल्कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सरकार की नैतिक बढ़त को भी कमजोर करता है। सरकारी सूत्रों का कहना है कि सरकार न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को आम सहमति के आधार पर हटाना चाहती थी। इसी के तहत लोकसभा में महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए आवश्यक 100 हस्ताक्षरों के मुकाबले 145 सांसदों ने समर्थन किया जिनमें विपक्ष के सदस्य भी शामिल थे लेकिन जानकारी के अनुसार उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जल्दबाजी में राज्यसभा को सूचित कर दिया कि न्यायमूर्ति वर्मा को हटाने का नोटिस प्राप्त हो गया है, यह उस समय हुआ जब लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने निचले सदन को इस बारे में कोई औपचारिक सूचना नहीं दी थी। मोदी सरकार के कार्यकाल में ही उन्हें राजभवन से लेकर उपराष्ट्रपति पद तक अभूतपूर्व शक्ति और सम्मान मिला था। ऐसे में अपने ही राजनीतिक संरक्षक के खिलाफ कदम उठाना उनके लिए तार्किक नहीं लगता। साथ ही उपराष्ट्रपति जैसे सर्वोच्च पद पर पहुंचने के बाद उनके पास विपक्ष के साथ खड़े होने का कोई राजनीतिक लाभ भी नहीं था। एक अन्य दृष्टिकोण यह भी है कि धनखड़ का इस्तीफा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उपराष्ट्रपति पद पर बैठाने की योजना का हिस्सा हो सकता है। यह संभावना पूरी तरह नकारी नहीं जा सकती लेकिन जिस जल्दबाजी में धनखड़ ने इस्तीफा दिया या उन्हें देने के लिए मजबूर किया गया वह भाजपा सरकार की कार्यशैली के विपरीत है। सरकार न तो किसी फैसले में जल्दबाजी करती है, न ही यूं फिसलती है।

अगर वास्तव में धनखड़ को हटाकर नीतीश कुमार को जगह देनी होती तो यह इस्तीफा संसद के मानसून सत्र से पहले हो सकता था न कि सुबह पद पर और दोपहर में बाहर जैसी स्थिति में। इसके अलावा सरकार को खुद को ऐसे असमंजस में डालने की कोई आवश्यकता नहीं थी जहां उसे ऐसे सवालों का सामना करना पड़े जिनके स्पष्ट जवाब उसके पास नहीं हैं। जैसे-जैसे घटनाएं सामने आ रही हैं, असली मुद्दा धनखड़ का जाना नहीं, बल्कि जिस तेजी से यह सब हुआ वही है जिसने सभी को चौंका दिया है।

# एक क्लिक में दुनिया से जुड़ने की क्रांति

**आज** के दौर में जब हर इंसान के हाथ में मोबाइल फोन है और हर सवाल का जवाब बस एक क्लिक की दूरी पर है, तब हम यह सोचने को मजबूर हो जाते हैं कि आखिर यह चमत्कारिक व्यवस्था कैसे अस्तित्व में आई? इंटरनेट तो एक विशाल महासागर है लेकिन उस महासागर तक पहुंचने का द्वार बना 'वर्ल्ड वाइड वेब' यानी www बिल्कुल साधारण से प्रतीत होने वाले इन तीन अक्षरों ने मानव जीवन को इस कदर बदल दिया है कि अब पूरी दुनिया में इसका कोई विकल्प ही नहीं बचा। इंटरनेट की यह जादुई खिड़की 1 अगस्त को एक प्रतीक के रूप में याद की जाती है 'वर्ल्ड वाइड वेब दिवस' के रूप में, ताकि हम उस विलक्षण मस्तिष्क को याद कर सकें, जिसने यह राह खोली। 'वर्ल्ड वाइड वेब' यानी www के जनक थे टिम बर्नर्स-ली। बचपन से ही तकनीक में गहन रुचि रखने वाले टिम बर्नर्स-ली का जन्म 8 जून 1955 को लंदन में हुआ था। 1976 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के क्वींस कॉलेज से स्नातक की पढ़ाई पूरी करते हुए उन्होंने मात्र 21 वर्ष की उम्र में ही स्वयं का एक कंप्यूटर सैट तैयार कर लिया था। टिम बर्नर्स-ली किसी सामान्य इंजीनियर की तरह केवल सीमित सोच तक नहीं रुके। वर्ष 1980 में जब वे एक निजी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर कार्यरत थे तभी उन्होंने कंप्यूटर में मौजूद दस्तावेजों और फाइलों को आपस में लिंक करने के लिए 'इन्क्वायर' नामक एक प्रयोगात्मक प्रोग्राम बनाया। यह उनकी एक छोटी-सी लेकिन दूरदर्शी सोच की नींव थी, जो बाद में पूरे विश्व को एक ही डिजिटल धागे में पिरोने वाली बन गई। बर्नर्स-ली की यह सोच सीमाओं में सिमटी हुई नहीं थी, बल्कि वे एक ऐसे वैश्विक सूचना तंत्र की कल्पना कर रहे थे जो समस्त कंप्यूटरों को आपस में जोड़ सके और वह लोगों के लिए सूचनाओं का एक व्यापक, सहज और सुलभ मंच बन जाए। इसी सपने को साकार करते हुए उन्होंने 1989 में 'वर्ल्ड वाइड वेब' की अवधारणा प्रस्तुत की और वर्ष 1991 में इस प्रणाली को सार्वजनिक रूप से लॉन्च किया। यह केवल तकनीकी प्रगति नहीं थी बल्कि यह मानव सभ्यता के इतिहास में एक नया मोड़ था जिसने संचार, शिक्षा, व्यापार, शोध और मनोरंजन की परिभाषा ही बदल दी। यह वही दौर था, जब इंटरनेट केवल टेक्स्ट तक सीमित था लेकिन 1993 के बाद इसमें चित्र, ग्राफिक्स और ऑडियो-वीडियो की सुविधा भी जुड़ने लगी जिससे इसकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ी और www एक वैश्विक जीवनशैली का हिस्सा बन गया। आज, वर्ल्ड वाइड वेब के बिना जीवन की कल्पना करना भी कठिन है। ऑफिस हो या स्कूल, बैंकिंग हो या अस्पताल, फिल्में देखनी हों या संगीत सुनना हो, किसी नए देश की जानकारी लेनी हो या कहीं की यात्रा करनी हो, प्रत्येक रास्ता www से होकर गुजरता है लेकिन इतना सब होते हुए भी यह कहना गलत नहीं होगा कि इस वेब का उपयोग तभी सार्थक है जब उपयोगकर्ता को सटीक जानकारी खोजने की कला आती हो क्योंकि यह वेब जितना विशाल है, उतना ही भ्रामक भी हो सकता है, यदि आप नहीं जानते कि जानकारी को ढूंढ़ना कैसे है। यही वह बिंदु है जहां सर्च इंजन नामक तकनीक हमारी राह आसान करती है। यह विशेष प्रोग्राम एक विशालकाय संग्रह की तरह है जो इंटरनेट पर मौजूद करोड़ों वेबसाइटों और उनके असंख्य पृष्ठों को स्कैन करके, हमारे सामने संबंधित परिणामों की सूची प्रस्तुत करता है। जब भी कोई उपयोगकर्ता किसी विषय पर जानकारी खोजता है, वह किसी सर्च इंजन, जैसे 'गूगल', 'याहू', 'बिंग' या भारतीय प्लेटफॉर्म 'खोज' में कुछ शब्द टाइप करता है और फिर वह सर्च इंजन अपने एल्गोरिद्म के जरिये करोड़ों पेजों को खंगालकर कुछ ही सैकेंड में उपयोगकर्ता के सामने सबसे प्रासंगिक जानकारी प्रस्तुत कर देता है। सर्च प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए उपयोगकर्ता विशेष चिन्हों का भी प्रयोग कर सकते हैं। उदाहरणस्वरूप यदि किसी विषय में दो या अधिक नामों को एक साथ खोजना हो तो उनके बीच '+' चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मोदी+शाह टाइप करने से वह पृष्ठ प्राथमिकता में सामने आएंगे, जिनमें दोनों नाम एक साथ होंगे। इसी प्रकार '-' का उपयोग उन शब्दों को हटाने के लिए किया जा सकता है जिनसे आप परिणामों को फिल्टर करना चाहते हैं। यह केवल तकनीकी जानकारी नहीं बल्कि डिजिटल युग में आत्मनिर्भर बनने का एक आवश्यक कौशल है। वर्ल्ड वाइड वेब की क्रांति के पीछे टिम बर्नर्स-ली का वह अद्वितीय और साहसिक विचार छिपा है जिसने मानव जीवन की दिशा ही बदल दी। उन्होंने वह कल्पना साकार की, जिसमें एक व्यक्ति किसी कमरे में बैठकर पूरी दुनिया की जानकारी अपनी स्क्रीन पर देख सकता है। यह केवल तकनीकी खोज नहीं थी बल्कि संचार की स्वतंत्रता, लोकतांत्रिक अभिव्यक्ति और ज्ञान की सार्वभौमिक पहुंच का एक शक्तिशाली माध्यम बन गई। वर्ल्ड वाइड वेब ने न केवल तमाम सीमाओं को मिटा दिया बल्कि सूचनाओं को मुक्त किया और एक वैश्विक समाज की नींव रखी, जिसे हम आज 'डिजिटल ग्राम' के रूप में जानते हैं। अब हर वर्ष जब हम 1 अगस्त को वर्ल्ड वाइड वेब दिवस मनाते हैं तो यह केवल एक तिथि नहीं होती बल्कि उस तकनीकी क्रांति को नमन करने का अवसर होता है जिसने मानव सभ्यता को नई रफ्तार दी। टिम बर्नर्स-ली का यह योगदान न केवल तकनीक के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में दर्ज है बल्कि यह भविष्य की तमाम तकनीकी क्रांतियों का मार्ग प्रशस्त करने वाली प्रेरणा भी है। वर्ल्ड वाइड वेब आज मानव संवाद, शिक्षा, शोध और लोकतंत्र का सशक्त प्रतीक बन चुका है।

## हिन्दू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता

**आपरेशन** सिन्दूर पर संसद में हुई चर्चा में हिस्सा लेते हुए केन्द्रीय गृहमंत्री श्री अमित शाह ने राज्यसभा में कहा कि 'मैं गर्व से कह सकता हूं कि कोई भी हिन्दू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता।' गृहमंत्री ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि वोट बैंक की राजनीति के लिए उसने भगवा आतंकवाद का झूठा सिद्धान्त बनाया। कांग्रेस ने बहुसंख्यक समुदाय को बदनाम करने की कोशिश की, लेकिन भारत की जनता ने इस झूठ को नकार दिया। शाह के इस ब्यान के बाद चर्चा छिड़ी है कि उन्होंने आखिर ऐसा दावा कैसे कर दिया कि हिन्दू कभी आतंकी नहीं हो सकता? पूछा जा रहा है कि उन्होंने भावावेश में आकर अतिकथनी कर दी या हिन्दू अस्मिता के प्रेम में फंस कर ये दावा कर दिया? अमित शाह का उक्त कथन उन लोगों के तो गले बिल्कुल नहीं उतर रहा जो अभी तक इसी विमर्श को पल्लवित-पोषित करते आ रहे हैं कि 'आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता', तो फिर कैसे हिन्दुओं को इस मामले में एकतरफा चरित्र प्रमाणपत्र दिया जा रहा है? निष्पक्ष हो कर अमित शाह के ब्यान को जांचा-परखा जाए तो सामने आता है कि इसमें न तो अतिरंजना है न मनोवेग या अतिश्योक्ति, बल्कि यह ऐतिहासिक सत्य, भारत-भूमि पर पनपा प्रामाणिक हिमालयी तथ्य है कि हिन्दू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता। आओ सबसे पहले जानें कि आतंकवाद आता कहां से है, इसका वीर्य क्या है? असल में विश्व में ईश्वर को लेकर दो तरह की अवधारणाएं या मार्ग हैं, एक सनातन व दूसरा सेमेटिक या सामी। सभी मार्ग सम्मानित हैं, पर इनमें मौलिक अन्तर है। सेमेटिक मजहब में ईश्वर का एक निश्चित संदेशवाहक या पैगम्बर या दूत, एक ही धर्म ग्रन्थ रहता है-जैसे इस्लाम, ईसाई व यहूदी मजहब। उक्त सभी मजहब अपने-अपने पैगम्बर को ईश्वर का अंतिम दूत और अपने-अपने धर्म ग्रन्थों में वर्णित बातों को ही ईश्वर का अंतिम सन्देश मानते हैं। सामी मजहब वाले केवल ऐसा मानते ही नहीं बल्कि अपने पैगम्बर व ग्रन्थों की बातों को दूसरे से श्रेष्ठ मानते हुए उन पर थोपने का प्रयास भी करते हैं। धीरे-धीरे इनके अनुयायियों में श्रेष्ठता की यही ग्रन्थी केवल मजहबी उन्माद तक ही सीमित नहीं रहती बल्कि रहन-सहन, खान-पीन, भाषा-वाणी अर्थात जीवन के हर क्षेत्र को संक्रमित कर देती है। दूसरे को हीन समझ उस पर अपने विचार व आस्था लादने के लिए कोई क्रूसेड करता है तो कोई जिहाद। दुनिया में ईसाईयत व इस्लाम के नाम पर जो अत्याचार, हिंसा, खूनखराबा हुआ सभी इसी श्रेष्ठता की ग्रन्थी के संक्रमण के चलते हुआ। दूसरे की आस्था के प्रति असम्मान, हिकारत, तिरस्कार में ही आतंकवाद के बीज छिपे रहते हैं। मध्ययुग में ईसाईयत के नाम पर आतंकवाद फैला परन्तु पश्चिमी समाज में आई नवचेतना के चलते इसने रूप बदल कर सेवा व लालच का ले लिया परन्तु इस्लाम के प्रचार-प्रसार का अमानवीय ढंग निरंतर जारी रहा, जिसे आज इस्लामिक आतंकवाद कहा जाने लगा है। आज ईसाई मिशनरीज सेवा व लालच के बल पर धर्मपरिवर्तन करते हैं और जिहादी बंदूक की नोक पर, दोनों का लक्ष्य एक ही है कि अपने-अपने मजहबों की संख्या बढ़ाना चाहे साधन अलग-अलग हैं। इस्लामिक जिहाद की तरह अगर ईसाइयों की सेवा व प्रलोभन के प्रपंचों को भी आतंकवाद का नाम दे दिया जाए तो कोई विषयभटकाव नहीं होगा।

**सम्पादकीय...**

## 'भगवा आतंकवाद' शब्द को गढ़ने वाले अब क्षमा मांगें

**जब** भगवा आतंकवाद जैसा शब्द जबरन गढ़ दिया गया था तब मैंने मेरी कांग्रेस मुक्त भारत की अवधारणा पुस्तक में लिखा था कि भगवा आतंकवाद जैसा कोई शब्द या टर्म हो ही नहीं सकता, यह एक अशब्द है जिसे हमें बोलचाल, लेखन व विमर्श से निकाल फेंकना होगा। इस शब्द को मप्र के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, केंद्र में एकाधिक विभागों के मंत्री रहे पी. चिदंबरम, तत्कालीन गृहमंत्री सुशील शिंदे और कांग्रेस ने केवल मोहरा बनकर गढ़ा था। इस शब्द के पीछे वस्तुतः तो वामपंथी छुपे हुए हैं जो प्रेत बनकर वेताल यानि कांग्रेस की पीठ पर अब भी सवार हैं। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनावों में जब भोपाल से साध्वी प्रज्ञा जी के विरुद्ध दिग्विजय सिंह चुनाव में उतरे थे तब उन्होंने समूचे चुनाव को 'भगवा आतंकवाद' को केंद्र में रखकर चुनाव लड़ा था। इस चुनाव के मध्य समाचार पत्रों में मेरा एक आलेख भी प्रकाशित हुआ था, जिसका शीर्षक था - 'भगवा आतंकवाद शब्द की अंत्येष्टि का सटीक समय'। इस चुनाव में जनता ने दिग्विजय सिंह को 'भगवा आतंकवाद' जैसा शब्द गढ़ने का यथोचित दंड दे दिया था। इस चुनाव में कम्युनिस्ट नेता सीताराम येचुरी भी भोपाल के सुंदर तालाब के किनारे पर बैठकर हिंदुत्व को मछली समझकर जाल डालकर बैठे हुए दिखे थे। उन्होंने भोपाल के ताल में एक नया शाब्दिक विष उंडेला था - हिंदू तो सदा से हिंसक रहा है। अरे, दिग्विजय जी, येचुरी जी, सहित भगवा आतंकवाद शब्द के सभी कथित नेताओं सुनो; हिंदू सदा से सहिष्णु रहा है, इतना सहिष्णु कि कई अवसरों पर इसका भूगोल और इतिहास ही बदल गया और कई अवसरों पर इस हिंदू सहिष्णुता ने हिंदुत्व के कुछ अध्यायों का समापन ही करवा दिया। यदि ऐसा नहीं होता तो, बाबर हजार मील दूर से भारत में आकर हमारे देश के आराध्य श्रीराम की जन्मभूमि पर बने मंदिर को नेस्तनाबूद कर बाबरी मस्जिद का निर्माण नहीं कर पाता। और, न ही दुर्दांत मुस्लिम शासक तैमूरलंग दिल्ली से हरिद्वार के समूचे मार्ग में हिंदू नरमुंड बिछा पाता, हिंदू हिंसक होता तो बख्तियार खिलजी भारतीय ज्ञान के प्रतीक, नालंदा को यूं आग के हवाले न कर पाता, न ही औरंगजेब काशी विश्वनाथ का मंदिर तोड़ पाता और न ही लाखों भारतीय मातृशक्ति को जौहर करने को मजबूर होना पड़ता। यदि हिंदू हिंसक होता तो गुरु गोविन्द सिंह के दोनों पुत्रों को जीवित दीवार में चुनकर मार डालने जैसी दुर्दांत घटना न हुई होती और न ही, मोहम्मद गजनवी श्रीकृष्ण जन्म स्थान को मथुरा में ध्वस्त कर कब्जा पाता। मालेगांव मामले में आए हुए निर्णय का मर्म यही है कि यदि हिंदू सहिष्णुता और उस पर हुए अत्याचारों का इतिहास और पढ़ना हो तो वे संत मतिदास को पढ़ लें, गुरु तेगबहादुर को पढ़ लें, जलियांवाला बाग पढ़ लें, भगतसिंह के बम फेंकने की मानवीय शैली पढ़ लें, भारत का धर्म आधारित विभाजन और उसके बाद यहां की भूमि पर मुस्लिमों की बसाहट व पाकिस्तान से हिन्दुओं का मारकाट भरा निर्वासन पढ़ लें, वे सोहरावर्दी पढ़ लें, मोपला काण्ड पढ़ लें। और यदि पुराना इतिहास न पढ़ना हो 'भगवा आतंकवाद' की माला जपने वाले नेताओं को हाल ही का 'रामसेतु विध्वंस' 'भगवान राम को काल्पनिक कहने का शपथपत्र' और 'ऐन दीवाली की रात्रि पूज्य शंकराचार्य जी की गिरफ्तारी का तालिबानी आदेश' पढ़ लेना चाहिए। इन घटनाओं सहित लाखों अन्य इतिहास सिद्ध घटनाओं ने यह ब्रह्मसत्य स्थापित किया है कि हिंदू हिंसक नहीं सहिष्णु रहा है, क्षमाशील रहा है, सर्वसमावेश को, सर्वस्पर्श को आतुर व उत्सुक समाज रहा है! मालेगांव के संदर्भ में कांग्रेसी नेताओं द्वारा यह भी कहा गया था कि आतंकवादी घटनाओं में मुस्लिमों से अधिक हिंदू सम्मिलित रहते हैं। 2008 के बाद, विशेषकर 26/11 के मुंबई हमले से ठीक पहले, मालेगांव केस को आधार बनाकर कम्युनिस्ट रिमोटेड कांग्रेसियों ने एक ऐसा नैरेटिव खड़ा किया था कि भारत में आतंकवाद को हिंदू संगठन बढ़ा रहे हैं। लेकिन यह एक वैचारिक आगजनी वाला झूठ था जो राजनीतिक लाभ के लिए रचा गया नैरेटिव, जिसकी कीमत निर्दोष हिंदुत्व के मासूम संतों, सैनिकों व नागरिकों ने चुकाई है। लेफ्ट-लिबरल मीडिया, कुछ स्वघोषित बुद्धिजीवी और वामपंथी इतिहासकारों ने इस नैरेटिव को खुलकर समर्थन दिया। प्रज्ञा ठाकुर, कर्नल श्रीकांत पुरोहित, स्वामी असीमानंद जैसे लोग, जो राष्ट्रवादी विचारधारा से जुड़े थे, उन्हें 'आतंकवादी' की तरह पेश किया गया, मीडिया ट्रायल चला, और तथाकथित सेकुलर ताकतों ने उनकी छवि को नष्ट-भ्रष्ट करने के प्रयास किए। साध्वी प्रज्ञा जी ठाकुर को गंभीर स्थिति के कैंसर की स्थिति में भी कारावास में रखा गया, उन्हें अमानवीय यातनाएं दी गईं। क्या इस पीड़ा के लिए कोई जिम्मेदार ठहराया जाएगा? क्या झूठे मुकदमों के लिए जांच एजेंसियों की जवाबदेही तय होगी? अब जब सच्चाई सामने आ चुकी है, तो वे चुप हैं। कोई आत्मचिंतन नहीं, कोई क्षमा नहीं। यह उनकी नैतिकता की हार है और इस देश के विवेक के लिए एक चेतावनी भी। आज की आवश्यकता है कि वे हिंदू समाज से उनके द्वारा गढ़े गए उन शब्दों के लिए क्षमा मांगें और उनका उत्तरदायित्व हमारा समाज तय करे। कांग्रेस नेतृत्व को अपने इस झूठे नैरेटिव गढ़ने के दोष हेतु देश से क्षमा मांगनी चाहिए। मालेगांव 2008, बम विस्फोट केस में कोर्ट द्वारा सभी आरोपियों को बाइज्जत बरी कर देना एक बहुत बड़ा न्यायिक पड़ाव है जो न केवल उन निर्दोषों के लिए, जिन्होंने वर्षों तक अपमान, पीड़ा और मानसिक प्रताड़ना को भोगा, बल्कि यह भारत की लोकतांत्रिक चेतना के लिए भी एक महत्वपूर्ण मोड़ है। न्यायालय ने स्पष्ट कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपों को साबित करने में असफल रहा। अब जब न्यायपालिका ने अपना निर्णय सुना दिया है, तब समय आ गया है कि इस केस के जरिए रची गई उस सुनियोजित 'राजनीतिक कथा' का गहराई से विश्लेषण किया जाए जो जिसे 'हिंदू आतंकवाद' कहा गया था। इस अभियान का मकसद स्पष्ट था – 'जिहादी आतंकवाद' से ध्यान हटाना और राष्ट्रवादी शक्तियों को कठघरे में खड़ा करना। उस समय पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद, विशेषकर मुंबई हमलों, संसद हमले, और कंधार कांड जैसे मामलों ने कांग्रेस सरकार की अंतरराष्ट्रीय छवि को प्रभावित किया था।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक विजय कुमार शास्त्री ने वन्दना ऑफसेट प्रिन्टर्स, ए-9, साउथ पीपलफाला एक्स. दिल्ली-33, से मुद्रित कर कार्यालय, बी-2/370, सुल्तानपुरी, दिल्ली-86 से प्रकाशित किया सम्पादक : विजय कुमार शास्त्री, मो. : 09582093548 समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं विवादास्पद केवल दिल्ली कोर्ट में होंगे। (DELHIN/2001/08862)

# रक्षाबंधन पर देवरिया की बेटियों ने दिखाया फर्ज़ का रिश्ता, सैनिकों के नाम भेजीं राखियाँ

देवरिया।

**जिलाधिकारी दिव्या मित्तल भी बनीं अभियान का हिस्सा, कहा यह धागा है विश्वास और देशभक्ति का**

जहां एक ओर रक्षाबंधन भाई-बहन के पवित्र प्रेम का प्रतीक है, वहीं देवरिया की बहनों ने इस पर्व को देशभक्ति से जोड़कर एक नई मिसाल पेश की है। शुक्रवार को स्वाद दरबार, गिन्नी प्लाज़ा, कैलाशपुरी में रोटरैक्ट क्लब देवरिया द्वारा आयोजित रक्षक बंधन ए राखी आफ ग्रेटीट्यूड टू आवर रियल हीरोज कार्यक्रम के माध्यम से हजारों राखियाँ सरहद पर तैनात जवानों को भेजी गईं। इस खास अवसर पर जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने कार्यक्रम में शिरकत कर न सिर्फ इस अभियान की सराहना की, बल्कि स्वयं भी सैनिकों के लिए राखियाँ भेजीं। उन्होंने कहा, राखी एक भावनात्मक बंधन है, जो आज देश के रक्षकों को देवरिया की बेटियों से जोड़ रहा है। यह न केवल एक पारंपरिक त्योहार है, बल्कि हमारे सैनिकों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का एक संवेदनशील जरिया भी है। जिलाधिकारी की उपस्थिति और सहभागिता ने बच्चों, शिक्षकों और समाजसेवियों में विशेष उत्साह भर दिया। कार्यक्रम में कई स्कूलों के छात्र-छात्राओं ने भी भाग लिया और खुद हाथों से बनाई गई राखियाँ सैनिकों के नाम भेजीं। कार्यक्रम स्थल पर देशभक्ति के गीतों और हाथों में तिरंगा लिए बच्चों का जोश देखते ही बन रहा था। रोटरैक्ट क्लब द्वारा चलाए जा रहे इस अभियान के तहत जिले भर से एकत्र की गई राखियों को विशेष पैकिंग के साथ डाक के माध्यम से भारतीय सेना के विभिन्न मोर्चों पर भेजा जा रहा है। आयोजकों ने बताया कि यह अभियान न केवल राखियाँ भेजने तक सीमित है, बल्कि बच्चों में राष्ट्रप्रेम और सैनिकों के प्रति सम्मान की भावना विकसित करने की दिशा में एक सार्थक प्रयास है।

# फाइलेरिया से बचाव का संकल्प, शिवाजी इंटर कॉलेज में बच्चों को किया गया जागरूकता

देवरिया।

**10 अगस्त से शुरू हो रहा सर्वजन दवा सेवन अभियान**

फाइलेरिया जैसी लाइलाज बीमारी से लड़ने के लिए अब स्कूली बच्चे भी तैयार हैं। भलुअनी ब्लॉक स्थित शिवाजी इंटर कॉलेज खुखुन्दु में शुक्रवार को एक खास जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हुआ, जहां पेशेंट स्टेक होल्डर प्लेटफार्म के सदस्यों ने छात्र-छात्राओं को फाइलेरिया से बचाव और एमडीए अभियान की उपयोगिता की जानकारी दी। कार्यक्रम के दौरान आयुष्मान आरोग्य मंदिर खुखुन्दु की सीएचओ गुंजन, एएनएम रिंकी व आशा संगिनी राधिका देवी ने विद्यार्थियों से संवाद करते हुए बताया कि फाइलेरिया एक गंभीर बीमारी है, लेकिन समय रहते इसके खिलाफ कारगर दवा सेवन से बचाव संभव है। उन्होंने बच्चों को सरल शब्दों में समझाया कि 'एक खुराक खाओ, फाइलेरिया भगाओ' सिर्फ नारा नहीं, एक जरूरी संकल्प है। जिला मलेरिया अधिकारी सीपी मिश्रा ने बताया कि फाइलेरिया का वायरस क्यूलेक्स मच्छर के काटने से फैलता है, और इसके लक्षण धीरे-धीरे वर्षों बाद सामने आते हैं। इसमें हाथ-पैर, अंडकोष या स्तनों में सूजन, भारीपन और विकृति जैसे लक्षण उभरते हैं। उन्होंने कहा कि इस बीमारी से बचने के लिए साल में सिर्फ एक बार दी जाने वाली दवा को पाँच वर्षों तक नियमित रूप से खाना जरूरी है। इस वर्ष यह अभियान 10 अगस्त से पूरे जिले में शुरू होगा, जिसमें आशा कार्यकर्ता घर-घर जाकर दवा खिलाएँगी। कार्यक्रम में उपस्थित छात्र-छात्राओं ने सामूहिक रूप से शपथ ली कि वे स्वयं दवा खाएँगे और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। उन्हें बताया गया कि यह दवा केवल भोजन के बाद ही लेनी है और खाली पेट बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। छात्रों को मच्छरों से बचाव के उपाय जैसे मच्छरदानी का प्रयोग, साफ-सफाई, जलभराव रोकना आदि के बारे में भी बताया गया।

**स्वर्गीय पंडित मातादीन शर्मा जयंती समारोह के अंतर्गत क्रीड़ा प्रतियोगिताओं का हुआ शुभारंभ**

पडरौना, कुशीनगर।

पडरौना नगर के हनुमान इंटरमीडिएट कॉलेज के संस्थापक स्वर्गीय पंडित माता दिन शर्मा के जयंती समारोह के अवसर पर कीड़ा प्रतियोगिताओं का शुभारंभ हुआ प्रतियोगिता में बालक एवं बालिकाओं की कबड्डी प्रतियोगिता एवं शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। प्रभारी जिला विद्यालय निरीक्षक श्रवण कुमार गुप्ता एवं प्रधानाचार्य डॉक्टर सुनीता पांडे, प्रधानाचार्य साधु शरण पांडे के द्वारा प्रतियोगिताओं का शुभारंभ कराया गया। अगन्तुको का स्वागत प्रबंधक मनोज शर्मा सारस्वत एवं आभार प्रधानाचार्य शैलेंद्र शुक्ला ने ज्ञापित किया। इस अवसर पर क्रीड़ा प्रभारी उशेष पांडे, सद्दाम हुसैन,सदरे आलम,विवेक, प्रदीप, सचिन, अमित, राहुल, मनोज, वंदना, सविता,सत्येंद्र, अवधेश, संध्या आदि उपस्थित रहे।

# बोस्टन अमेरिका में वैश्विक विधायी सम्मेलन में हिस्सा लेंगे विधायक पीएन पाठक

कसया,कुशीनगर।

उत्तर प्रदेश के विधायक/विधान परिषद सदस्यों का एक प्रतिनिधिमंडल बोस्टन अमेरिका में होने वाले वैश्विक विधायी सम्मेलन में हिस्सा लेने जा रहे हैं, जिसमें कुशीनगर विधानसभा क्षेत्र के विधायक पीएन पाठक भी है। बता दें कि वैश्विक स्तर पर विधायकों के सहयोग को बढ़ाने के लिए एक खास पहल के तहत, विधायक पीएन पाठक जो विधानसभा क्षेत्र कुशीनगर के विधायक हैं, बोस्टन, अमेरिका में 4 से 6 अगस्त 2025 को होने वाले National Conference of State Legislatures (NCSL) द्वारा आयोजित इस बड़े सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं।भारतीय विधायकों का यह अध्ययन दौरा National Legislators Conference Bharat (NLC भारत) के सहयोग से संभव हो पा रहा है। NLC Bharat एक गैर-राजनीतिक मंच है, जो भारतीय विधायकों की क्षमता बढ़ाने और राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय लोकतांत्रिक बातचीत को बढ़ावा देने के लिए काम करता है। यह समूह 24 राज्यों और 21 राजनीतिक दलों के 130 से ज्यादा विधायकों (MLAs और MLCs) का है, जो किसी भी अंतरराष्ट्रीय लोकतांत्रिक मंच पर भारत की अब तक की सबसे बड़ी भागीदारी को दर्शाता है।

यह पहल लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए देशों के बीच बातचीत, सहयोग और ज्ञान साझा करने की भावना को दिखाती है।इस मौके पर विधायक पीएन पाठक ने कहा कि मेरे राज्य और क्षेत्र का प्रतिनिधित्व वैश्विक मंच पर करना गर्व की बात है। यह अवसर न केवल अंतरराष्ट्रीय अनुभव का है, बल्कि वैश्विक सुशासन की अच्छी परंपराओं से सीखने और उन्हें जनता की सेवा में लाने का मौका है। मैं NLC भारत और इसके संस्थापक Dr. Rahul V. Karad का इस अनुभव के लिए दिल से धन्यवाद देता हूँ। सम्मेलन में यह समूह दुनिया भर के 6000 से ज्यादा विधायकों के साथ बातचीत करेगा और Artificial Intelligence, Digital Democracy, Cyber Security, Voter Confidence and Policy Innovation जैसे आधुनिक विषयों पर चर्चा में हिस्सा लेगा। साथ ही, अमेरिकी विधायी प्रणाली के बारे में जानकारी और अमेरिका में भारतीय मूल के नेताओं के साथ बातचीत भी इस यात्रा का हिस्सा है।यह भागीदारी भारत के लोकतांत्रिक नेतृत्व की वैश्विक मंच पर मजबूत उपस्थिति और निरंतर विकास की इच्छा को दिखाती है।

# मंदिर में जलाभिषेक के साथ हुआ वृक्षारोपण

**पडरौना कुशीनगर।** सावन के महीने में मारवाड़ी युवा मंच चेतना महिला शाखा पडरौना की सदस्याओं द्वारा कुबेरस्थान शिव मंदिर में जलाभिषेक का कार्यक्रम किया गया।मंच की सभी सदस्यों द्वारा लाल पीले परिधान धारण करके शिव मंदिर में कतार बद्ध होकर शिवलिंग पर दूध फल फूल बेलपत्र घी दही धतूरा पानी आदि से भगवान भोले की पूजा अर्चना की गई। मंच अध्यक्ष मीनू जिंदल ने कहा कि सावन में इस भक्ति पूर्ण कार्यक्रम करने का उद्देश्य भक्तों की मनोकामना पूरी होने से है। पूजन अर्चन के बाद मंदिर परिसर में ही वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से मंत्री रश्मि टिबड़ेवाल कोषाध्यक्ष प्रिया टिबड़ेवाल नीलम अग्रवाल नीलम रुंगटा दीपा अग्रवाल अनीता टिबरड़ेवाल मधु नथानी नीतू खेतान अनीता बगड़िया पदमा अग्रवाल सविता टिबड़ेवाल आदि सम्मिलित हुईं।

# सेवा निवृत्त बैंक कर्मी को दी गई विदाई

**खोड्डा बाजार कुशीनगर।** पंजाब नेशनल बैंक शाखा खोड्डा से हेड कैशियर पद से सेवा निवृत्त हुए अवधेश मिश्रा बहुत ही सरल स्वभाव व मृदुभाषी हैं जो कि अपनी सेवा से निवृत हुए उनके विदाई समारोह में क्षेत्र के बहुत सारे सम्मानित लोग उपस्थित हुए। अवधेश मिश्रा ने कहा सेवा निबृति एक सतत प्रक्रिया है कोई भी व्यक्ति अपने सेवा से निवृत होता है अपने कार्यों से नही मुक्त हो पाता है। इस मौके पर शाखा प्रबंधक समीर कुमार, पूर्व में रहे शाखा प्रबंधक रवि रंजन कुमार पवन कुमार सिंह ग्राम प्रधान प्रवीण कुमार सिंह, खोड्डा ग्राम प्रधान प्रवीण सिंह,पकड़ी अरुष पाण्डेय, रविन्द्र यादव, पटेश्वर यादव,बिजेंद्र कुमार रवि सिंह शेतभान चौरसिया मंटू सिंह लालमनी,आदि सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित रहे।

# वृद्धाश्रम में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा भजन-भोजन व फल वितरण कार्यक्रम सम्पन्न

जौनपुर ।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉ. गोरखनाथ पटेल के नेतृत्व में आज जिला बेसिक शिक्षा कार्यालय की ओर से एक सराहनीय सेवा कार्य का आयोजन किया गया। इस अवसर पर डॉ. पटेल एवं कार्यालय के समस्त कार्मिक वृद्धाश्रम पहुंचे, जहां सभी वृद्धजनों को भजन-भोजन कराकर फल वितरित किए गए। कार्यक्रम के दौरान जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सहित समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने वृद्धजनों से उनकी कुशल-क्षेम भी जानी और उन्हें स्नेहपूर्वक आत्मीयता प्रदान की। कार्यक्रम ने सामाजिक सरोकारों के प्रति शिक्षा विभाग की संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता को दर्शाया। कार्यक्रम के समापन पर डॉ. गोरखनाथ पटेल द्वारा सभी उपस्थित वृद्धजनों एवं गणमान्य व्यक्तियों को अंगवस्त्र भेंटकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर वरिष्ठ सहायक श्री विंध्यवासिनी उपाध्याय ने डॉ. पटेल को एक भेंट-चित्र देकर आभार व्यक्त किया। इस सेवा कार्यक्रम में कार्यालय के सहायक वित्त एवं लेखा अधिकारी श्री आलोक गुप्ता, समस्त जिला समन्वयकगण एवं अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण की भी गरिमामयी उपस्थिति रही।

**तुलसी मानस पंच तंत्र अवार्ड से विभूषित किये गये श्रीप्रकाश शुक्ला**

सुजानगंज, जौनपुर। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास के अवतरण दिवस थाणे मुंबई में बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम का आयोजन मानस प्रयास सेवा संस्थान द्वारा गंगूबाई शिंदे हाल में किया गया। कार्यक्रम के दौरान तुलसी मानस पंच तंत्र अवार्ड विभूति-2025 सम्मान से सुजानगंज ब्लॉक प्रमुख श्रीप्रकाश शुक्ल, वरिष्ठ साहित्यकार राजेश विक्रांत और प्रख्यात विचारक नम्रता सीताराम देशमुख को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान स्वामी समर्थ रामदास जी महाराज, भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ल, उद्योगपति सुरेंद्र शुक्ल, पंकज मिश्र, सुरेंद्र उपाध्याय, गिरीश गोपालन, शैलेश सिंह, धर्मेन्द्र पांडेय, पंकज पांडेय सहित तमाम गणमान्य उपस्थित थे।

# देवेंद्र यादव ने एलजी और मेयर को लिखा पत्र, जर्जर हैं स्कूल के हालात, खतरे में 7 लाख बच्चों की जान

नई दिल्ली। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने दिल्ली नगर निगम के 1500 से अधिक प्राथमिक स्कूलों की जर्जर हालत पर चिंता व्यक्त करते हुए उपराज्यपाल विनय सक्सेना और मेयर राजा इकबाल सिंह को पत्र लिखकर लिखा. उन्होंने पत्र में मासूम बच्चों की जिंदगी बचाने के लिए निगम स्कूलों की खतरनाक हालात को सुधारने के लिए तुरंत हस्तक्षेप की मांग की. उन्होंने पत्र के माध्यम से बताया कि 30-50 साल पुराने भवनों में चल रहे 1500 में से चल 1185 स्कूलों में पढ़ने वाले लगभग 7.8 लाख छात्रों का जीवन संकट में है. देवेंद्र यादव ने बताया कि 16 जुलाई को स्थाई समिति की बैठक में स्कूलों की जर्जर हालत और स्कूल भवनों में पानी भरने का मामला उठाया, परंतु कोई ठोस निर्णय सामने नहीं आया. उन्होंने कहा कि दिल्ली नगर निगम क्या राजस्थान के झालावाड़ जिला के पीपलोदी गांव के स्कूल हादसे जैसी घटना का इंतजार कर रहा है, जहां स्कूल की छत गिरने पर 7 बच्चों की मौत हो गई. देवेंद्र यादव ने कहा कि इस साल निगम स्कूलों के लिए 1693 करोड़ से अधिक बजट का प्रावधान है, जो पिछले साल के बजट से 48.2 करोड़ अधिक है. जब दिल्ली नगर निगम के 1185 स्कूलों में से 368 स्कूल जर्जर हालत में है और बाकी स्कूलों में भी उपयुक्त रख-रखाव और मरम्मत की जरूरत है. उन्होंने कहा कि फिर निगम के 12 जोनों में चलने वाले एक भी स्कूल के भवन की मरम्मत के लिए कोई काम क्यों नहीं हुआ? जहां पहाड़गंज जोन के 75 स्कूलों में 26 भवन जर्जर हालत में है, करोल बाग जोन के 69 स्कूलों में 23 भवन जर्जर है. उन्होंने दावा किया कि केशव पुरम जोन के 89 स्कूलों में 35 भवन जर्जर है. शाहदरा साउथ जोन के 127 स्कूलों में 33 भवन जर्जर है. शाहदरा नॉर्थ जोन के 103 स्कूलों में 14 भवन जर्जर है. रोहिणी जोन के 80 स्कूलों में 23 भवन जर्जर है. नजफगढ़ जोन के 110 स्कूलों में 36 भवन जर्जर है. नरेला जोन के 145 स्कूलों में 26 भवन जर्जर है. सिविल लाइंस जोन के 71 स्कूलों में 9 भवन जर्जर है. सेंट्रल जोन के 94 स्कूलों में 53 भवन जर्जर है. साउथ जोन के 120 स्कूलों में 59 भवन जर्जर है. वेस्ट जोन के 102 स्कूलों में 31 भवन पूरी तरह जर्जर हालत में है. देवेंद्र यादव ने कहा कि राजधानी में नंद नगरी, लामपुर, नरेला, सनौठ गांव, मंगोलपुरी, मैदान नगर, मोहम्मदपुर गांव, कृष्णा पंडित, नांगलोई के स्कूलों की जर्जर हालत और अग्नि सुरक्षा के इंतजाम न होने की खबरें और तस्वीरें अखबारों और मीडिया में उजागर होने के बावजूद कोई बयान नहीं आया है. उन्होंने कहा कि 30 प्रतिशत स्कूल खतरनाक है और कभी भी गिरने की हालत में है, फिर भी उनका संचालन किया जा रहा है, जिस पर दिल्ली नगर निगम द्वारा तुरंत कार्रवाई करने की जरूरत है. देवेंद्र यादव ने कहा कि निगम स्कूल की बिल्डिंग गिरने की घटनाएं हर साल हो रही है. इस साल 17 मई को मोतिया खान चौक के पास हरि मंदिर स्कूल की दीवार गिर गई, जिससे 5 कारें क्षतिग्रस्त हो गईं. 10 अगस्त 2024 को डिफेंस क्षेत्र में भारी बारिश के कारण निगम स्कूल की दीवार गिरने से 2 लोग घायल हो गए. उन्होंने कहा कि 12 अगस्त 2024 को अशोक नगर के सरकारी स्कूल की दीवार गिरने से कई वाहन क्षतिग्रस्त हुए. 23 सितम्बर 2023 को पूर्वी दिल्ली के दिलशाद गार्डन क्षेत्र में बारिश के दौरान स्कूल की दीवार गिरने से 11 वाहन क्षतिग्रस्त हुए.

# अफसर वोटों की चोरी करा रहे - राहुल

## हम छोड़ेंगे नहीं, चाहे वे रिटायर हो जाएं; हमारे पास एटम बम, जब फटेगा तो चुनाव आयोग बचेगा नहीं

नई दिल्ली ।

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के आरोपों पर अब चुनाव आयोग ने पलटवार किया है. चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के आरोपों को बेबुनियाद बताया है. साथ ही कहा कि चुनाव आयोग रोज-रोज लगाए जा रहे ऐसे बेबुनियाद आरोपों को नजरअंदाज करता है.

चुनाव आयोग ने चुनावकर्मियों को ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयानों पर ध्यान नहीं देने के लिए कहा है. राहुल गांधी ने शुक्रवार को बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर चुनाव आयोग पर बड़ा आरोप लगाया था और दावा किया था कि चुनाव आयोग वोट चोरी करवा रहा है. साथ ही कहा था कि रिटायरमेंट के बाद भी अधिकारियों को छोड़ा नहीं जाएगा.

राहुल गांधी के आरोपों पर पलटवार करते हुए चुनाव आयोग ने कहा कि चुनाव आयोग रोज-रोज लगाए जा रहे ऐसे बेबुनियाद आरोपों को नजरअंदाज करता है और रोज-रोज दी जा रही धमकियों के बावजूद निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से कार्य कर रहे सभी चुनावी कर्मियों को ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयानों पर ध्यान नहीं देने के लिए कहता है.

**वोट चोरी हो रही है, हमारे**

### आरोप बेबुनियाद, चुनाव अधिकारी ऐसी धमकियों को नजरअंदाज करें -ईसी

**पास पुख्ता सबूत: राहुल गांधी**

राहुल गांधी ने शुक्रवार को बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर चुनाव आयोग पर बड़ा आरोप लगाया था और दावा किया था कि चुनाव आयोग वोट चोरी करवा रहा है. कांग्रेस के शीर्ष नेता ने संसद परिसर में संवाददाताओं से कहा, ''मैंने बोला है कि वोट चोरी हो रही है. अब हमारे पास एकदम पुख्ता सबूत है कि निर्वाचन आयोग वोट चोरी में शामिल है. मैं हल्के-फुल्के अंदाज में नहीं बोल रहा हूं, मैं 100 प्रतिशत सबूत के साथ बोल रहा हूं.

**आप हिंदुस्तान के खिलाफ काम कर रहे हो- राहुल गांधी**

उन्होंने दावा किया, ''हम जैसे ही यह जारी करेंगे, पूरे देश को पता लग जाएगा कि आयोग वोट चोरी करा रहा है और वह भाजपा के लिए करा रहा है.

राहुल गांधी ने चेतावनी भरे लहजे में कहा, ''मैं बड़ी गंभीरता से बोल रहा हूं कि निर्वाचन आयोग में जो भी यह काम कर रहे हैं, आपको हम छोड़ेंगे नहीं. आप हिंदुस्तान के खिलाफ काम कर रहे हैं, यह राष्ट्रद्रोह है. आप सेवानिवृत्त हो गए हों, या कहीं भी हों, आपको ढूंढ़कर निकालेंगे.

# संवैधानिक संस्थाओं को धमका रहे राहुल गांधी - किरेन रिजिजू

नई दिल्ली । केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने शुक्रवार को कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला और उन पर भारत विरोधी भाषा का इस्तेमाल करने और लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने का आरोप लगाया। रिजिजू ने कहा कि विपक्ष के सदस्य भी गांधी की टिप्पणी की आलोचना कर रहे हैं, खासकर भारत को बर्बाद अर्थव्यवस्था बताने की उनकी टिप्पणी की।

रिजिजू ने कहा कि राहुल गांधी की भारत विरोधी भाषा का विपक्ष के कई प्रमुख लोग भी विरोध कर रहे हैं। वे यह भी कहते हैं कि आप भारत को बर्बाद अर्थव्यवस्था नहीं कह सकते। रिजिजू ने गांधी से अपनी भूमिका के अनुरूप जिम्मेदारी से काम करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को पता होना चाहिए कि वह कोई छोटे बच्चे नहीं हैं। उन्हें विपक्ष के नेता की तरह व्यवहार करना चाहिए। रिजिजू ने विपक्ष पर जानबूझकर संसदीय कार्यवाही बाधित करने का आरोप लगाते हुए तर्क दिया कि इसका नुकसान अंततः विपक्षी सांसदों को ही हो रहा है।

उन्होंने कहा, विपक्ष सदन को चलने नहीं दे रहा है। सबसे ज्यादा नुकसान विपक्षी सांसदों को हो रहा है, जो जनता के मुद्दे नहीं उठा पा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के उपसभापति, दोनों ने स्पष्ट कर दिया है कि चर्चा संसदीय नियमों के दायरे में ही होनी चाहिए। मंत्री ने आरोप लगाया कि यह पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी संवैधानिक संस्थाओं को धमका रहे हैं। यह लोकतंत्र को कमजोर करने की एक बड़ी साजिश है। यह बेहद खतरनाक व्यवहार और रवैया है। विपक्ष संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करने की कुत्सित योजना चला रहा है। यह लोकतंत्र पर हमला है... यहां तक कि विपक्षी दल के नेता भी राहुल गांधी का आंतरिक विरोध करने लगे हैं... लोग कहने लगे हैं कि राहुल एक गंदा खेल खेल रहे हैं और देश की छवि खराब करना चाहते हैं।

# पूर्व जेडीएस सांसद प्रवल रेवन्ना रेप मामले में दोषी करार

### कोर्ट से रोते हुए बाहर निकला, आज सजा का ऐलान; मेड का शोषण किया था

नई दिल्ली । बेंगलुरु की एक विशेष अदालत ने शुक्रवार को पूर्व सांसद प्रवल रेवन्ना को यौन शोषण और बलात्कार के मामले में दोषी ठहराया। पूर्व जेडी(एस) नेता को कर्नाटक के हासन जिले के होलेनरसिपुरा ग्रामीण पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ दर्ज पहले बलात्कार मामले में दोषी ठहराया गया। बेंगलुरु स्थित जनप्रतिनिधियों की विशेष अदालत ने 18 जुलाई को बलात्कार मामले की सुनवाई पूरी कर ली थी और अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। सजा का ऐलान शनिवार, 2 अगस्त को होगा। रेवन्ना पिछले साल दर्ज किए गए चार आपराधिक मामलों में मुख्य आरोपी है, जब सोशल मीडिया पर कथित तौर पर कई महिलाओं के यौन शोषण को दर्शाने वाले 2,000 से ज्यादा अश्लील वीडियो क्लिप सामने आए थे। पहली शिकायत अप्रैल 2024 में एक महिला ने दर्ज कराई थी, जो उनके परिवार के फार्महाउस में घरेलू सहायिका के रूप में काम करती थी। उसने रेवन्ना पर 2021 से बार-बार बलात्कार करने और किसी को भी घटना के बारे में बताने पर दुर्व्यवहार के वीडियो जारी करने की धमकी देने का आरोप लगाया था।

# आयोग ने जारी किया नोटिफिकेशन 9 सितंबर को होगा उपराष्ट्रपति पद का चुनाव

नई दिल्ली । जगदीप धनखड़ के पद से इस्तीफा देने के कुछ दिनों बाद, चुनाव आयोग ने शुक्रवार को उपराष्ट्रपति पद के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की। चुनाव आयोग द्वारा जारी एक अधिसूचना में कहा गया है कि 17वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान 9 सितंबर को होगा। अधिसूचना में कहा गया है कि चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 21 अगस्त, गुरुवार है, जबकि उम्मीदवार अधिकतम 25 अगस्त तक अपना नाम वापस ले सकते हैं। 22 जुलाई को निवर्तमान अध्यक्ष जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद यह चुनाव आवश्यक हो गया था।

चुनाव आयोग की अधिसूचना जारी होने की तिथि- 7 अगस्त, 2025 (गुरुवार)।

नामांकन की अंतिम तिथि- 21 अगस्त, 2025 (गुरुवार)।

नामांकन की जांच की तिथि- 22 अगस्त, 2025 (शुक्रवार)।

नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि- 25 अगस्त, 2025 (सोमवार)।

मतदान की तिथि (यदि आवश्यक हो)- 9 सितंबर, 2025 (मंगलवार)।

मतगणना की तिथि (यदि आवश्यक हो)- 9 सितंबर, 2025 (मंगलवार)।

यह घोषणा जगदीप धनखड़ के 21 जुलाई को उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने के बाद हुई है, जिससे उनके उत्तराधिकारी के लिए प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई है। 74 वर्षीय धनखड़ ने अगस्त 2022 में पदभार ग्रहण किया था और उनका कार्यकाल 2027 तक था। धनखड़ के अचानक इस्तीफे के बाद राज्यसभा में सरकार के लिए एक दिन का चौंकाने वाला घटनाक्रम सामने आया, जब इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यशवंत वर्मा को हटाने के लिए विपक्ष द्वारा प्रायोजित एक प्रस्ताव का नोटिस उन्हें सौंपा गया और उन्होंने सदन में इसका उल्लेख किया।

# बाल श्रम को लेकर कार्रवाई की तैयारी में योगी सरकार, तैयार कीं संकटग्रस्त बच्चों की सहायता से जुड़ी योजनाएं

लखनऊ।

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य को बाल श्रम से पूरी तरह मुक्त कराने के लिए व्यापक और चरणबद्ध रणनीति तैयार की है। सीएम योगी के नेतृत्व में श्रम विभाग ने इससे जुड़ी राज्य कार्ययोजना तैयार की है और इसके केंद्र में महिला एवं बाल विकास विभाग को रखा गया है, जो न केवल संकटग्रस्त बच्चों की पहचान और सहायता करेगा, बल्कि उनके पुनर्वासन के हर स्तर पर प्रमुख भूमिका निभाएगा। प्रदेश सरकार का लक्ष्य है कि दिसंबर 2026 तक प्रदेश के आठ आकांक्षी जनपदों- बहराइच, बलरामपुर, चंदौली, चित्रकूट, फतेहपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर और सोनभद्र को बाल श्रम से मुक्त कर दिया जाएगा। इसके साथ ही कानपुर मंडल और देवीपाटन मंडल में भी विशेष बाल श्रम विरोधी अभियान चलाया जाएगा। महिला एवं बाल विकास विभाग के तहत वन स्टॉप सेंटर, बाल सेवा योजना और स्पॉन्सरशिप योजना जैसी योजनाओं को बाल श्रमिकों के पुनर्वासन में प्रभावी रूप से उपयोग में लाया जाएगा। वन स्टॉप सेंटर के जरिए संकट में फंसे बच्चों को अस्थायी आश्रय देने की योजना तय की गई है। साथ ही इनमें बच्चों की पहचान, स्वास्थ्य जांच, परामर्श और समाज में पुनर्स्थापन की भी व्यवस्था करना तय किया गया है।

# मैनपुरी में भीषण कार हादसा, एक ही परिवार के पांच लोगों की दर्दनाक मौत

मैनपुरी। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले में शुक्रवार को एक भीषण हादसा हो गया। इस हादसे में कार सवार एक ही परिवार के पांच लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। बेवर थाना क्षेत्र के जीटी रोड हाईवे पर अचानक अनियंत्रित हुई स्विफ्ट कार डिवाइडर पार करते हुए सामने से आते ट्रक में जा घुसी। हादसे में कार सवार एक ही परिवार के पांच लोगों की मौत हो गई, जबकि एक बालिका गंभीर रूप से घायल हो गई। सभी लोग आगरा से जन्मदिन पार्टी कर छिबरामऊ स्थित घर लौट रहे थे। हादसे के बाद वाहनों की लंबी-लंबी लाइन लगने से एक घंटे तक जाम लग गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर जाम खुलवाया और आवागमन सुचारू कराया।

# पुणे के दौंड में आपत्तिजनक पोस्ट के बाद तनाव

### धार्मिक स्थल पर पथराव, गाड़ियों को आग लगाई; शिवाजी महाराज के अपमान में प्रदर्शन हो रहा था

पुणे । पुणे के दौंड में शुक्रवार को सोशल मीडिया पर एक आपत्तिजनक पोस्ट के बाद तनाव बढ़ गया है। दो गुटों की भीड़ ने सड़कों पर कई गाड़ियों को आग लगा दी गई। धार्मिक स्थल पर पथराव किया है। घटना पुणे से 80 किमी दूर दौंड के यवत गांव की है। तनाव को देखते हुए यवत का साप्ताहिक बाजार बंद कर दिया गया है। पुलिस ने हालात को काबू पाने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। यवत पुलिस निरीक्षक नारायण देशमुख ने बताया कि आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले युवक का नाम सैय्यद है और हिरासत में ले लिया है। दरअसल, 26 जुलाई को यवत के नीलकंठेश्वर मंदिर में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा के साथ तोड़फोड़ की घटना हुई थी। इसी को लेकर गुरुवार से ही विरोध हो रहा था। इसी विवाद पर शुक्रवार को एक युवक की आपत्तिजनक पोस्ट वायरल हो गई। इसके बाद प्रदर्शनकारी यवत के सहकार नगर में युवक के घर पहुंचे और तोड़फोड़ की। तभी दो पक्षों में टकराव हो गया और तनाव की स्थिति बन गई।

**पुलिस अधिकारी बोले- अब हालात काबू में है**

पुलिस अधिकारी ने बताया कि यवत इलाके में पुलिस बल की तैनाती बढ़ा दी है। हालात काबू में है। पुणे ग्रामीण के पुलिस अधीक्षक संदीप सिंह गिल ने तनाव वाले इलाकों में पहुंचे हैं। उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। पुलिस प्रशासन ने मोर्चा संभाल लिया है और गांव में गश्त की जा रही है। स्थिति अभी शांतिपूर्ण है। उन्होंने अफवाह फैलाने वालों को चेतावनी भी दी।

# स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से गूंजेगी जनता की आवाज़! पीएम मोदी ने भाषण के लिए मांगा आईडिया

नई दिल्ली । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को देश भर के नागरिकों से इस वर्ष के स्वतंत्रता दिवस संबोधन के लिए अपने विचार और सुझाव साझा करने का आह्वान किया। X पर एक पोस्ट में, प्रधानमंत्री मोदी ने जनता से MyGov.in और NaMo ऐप पर खुले मंचों के माध्यम से अपने विचार साझा करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने लिखा, जैसे-जैसे हम इस वर्ष के स्वतंत्रता दिवस के करीब पहुंच रहे हैं, मैं अपने साथी भारतीयों से सुनने के लिए उत्सुक हूं!

आप इस वर्ष के स्वतंत्रता दिवस भाषण में किन विषयों या विचारों को प्रतिबिंबित होते देखना चाहेंगे? MyGov और NaMo ऐप पर खुले मंचों पर अपने विचार साझा करें।

परंपरा के अनुसार, भारत के प्रधानमंत्री हर साल 15 अगस्त को दिल्ली के लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं और राष्ट्र को संबोधित करते हैं।

पिछले साल, भारत के 78वें स्वतंत्रता दिवस पर, प्रधानमंत्री मोदी का भाषण विकसित भारत @2047 विषय पर केंद्रित था, जो 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के सरकार के दृष्टिकोण को रेखांकित करता है। प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत, जीवन को आसान बनाने, वायु सेना में महिलाओं की भूमिका, राजनीति में भाई-भतीजावाद से निपटने, बांग्लादेशी हिंदुओं की सुरक्षा, समान नागरिक संहिता के विचार और 2036 ओलंपिक की मेजबानी करने की भारत की आकांक्षाओं सहित कई प्रमुख मुद्दों पर भी बात की। औपचारिक परंपराओं को जारी रखते हुए, प्रधानमंत्री ने राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की और राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद राष्ट्रीय सलामी प्राप्त की। पिछले वर्ष, पंजाब रेजिमेंट के सैन्य बैंड द्वारा सलामी दी गई थी, जिसमें सूबेदार मेजर राजिंदर सिंह के नेतृत्व में एक जेसीओ और 25 अन्य रैंक के सैनिक शामिल थे। इस वर्ष प्रधानमंत्री मोदी लाल किले से लगातार 12वीं बार स्वतंत्रता दिवस पर भाषण दे रहे हैं, जिससे वे जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के बाद यह उपलब्धि हासिल करने वाले केवल तीसरे भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं।

# विपक्ष का वोटर वेरिफिकेशन को लेकर हंगामा, नहीं चल सके दोनों सदन

नई दिल्ली। बिहार में मतदाता सूची संशोधन पर विशेष चर्चा की मांग को लेकर विपक्षी सांसदों के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित रही। हंगामे के बीच लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही सोमवार, 4 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी गई। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी समेत कई विपक्षी दलों के नेताओं ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर बिहार में चल रहे विशेष सर्वेक्षण पर बिना किसी देरी के एक विशेष चर्चा कराने का आग्रह किया है। इस बीच, विपक्षी भारतीय ब्लॉक के सांसदों ने शुक्रवार को संसद में मकर द्वार के सामने विरोध प्रदर्शन किया और चर्चा की मांग की।

**लोकसभा की कार्यवाही**

- बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के मुद्दे पर शुक्रवार को लोकसभा में विपक्षी दलों के सदस्यों के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद सोमवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कार्यवाही स्थगित करने से पहले शोर-शराबा कर रहे सदस्यों से कहा, ''जनता ने आपको इतना बड़ा अवसर दिया है, इसे नारेबाजी करके और तख्तियां दिखाकर मत गंवाइए।'' सदन की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद अपराह्न दो बजे फिर से शुरू होते ही विपक्षी सदस्य आसन के निकट पहुंचकर 'एसआईआर वापस लो' के नारे लगाने लगे।



**राज्यसभा की कार्यवाही**

देश की सुरक्षा एवं उसके हितों को सर्वोपरि बताते हुए सरकार ने कहा कि बांग्लादेश को उसके यहां सल्तनत-ए-बांग्ला समूह के सक्रिय होने के कोई सबूत नहीं मिले। समूह द्वारा बनाये गये तथाकथित 'ग्रेटर बांग्लादेश' के नक्शे में भारत के कुछ हिस्सों को शामिल गया गया है। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रह्मण्यम जयशंकर ने राज्यसभा को एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह भी बताया कि यह नक्शा ढाका विश्वविद्यालय में प्रदर्शित किया गया था। सरकार ने शुक्रवार को बताया कि नयी वंदे भारत तथा अमृत भारत ट्रेनों को दिव्यांगजनों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राज्यसभा को दिए एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। पूर्वाह्न 11 बजे बैठक शुरू होने पर उपसभापति हरिवंश ने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए। उन्होंने बताया कि उन्हें नियम 267 के तहत 30 नोटिस मिले हैं जिनमें बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर), ओडिशा में महिलाओं और बच्चों के कथित उत्पीड़न, बंगाली कामगारों के साथ दूसरे राज्यों में कथित दुर्व्यवहार, छत्तीसगढ़ में दो नन्नों की गिरफ्तारी, अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए 25 फीसदी शुल्क और जुर्माने के दुष्प्रभाव के मुद्दे पर नियत कामकाज स्थगित कर तत्काल चर्चा कराए जाने की मांग की गई है। उपसभापति ने कहा कि ये नोटिस आसन द्वारा पूर्व में दी गई व्यवस्था के अनुरूप नहीं है, इसलिए इन्हें स्वीकार नहीं किया जा सकता। नोटिस स्वीकार नहीं किए जाने पर विपक्षी सदस्यों ने विरोध जताया और हंगामा करने लगे। तृणमूल कांग्रेस के कुछ सदस्य आसन के सामने आ कर ''एसआईआर पर हल्ला बोल'' तथा ''वोट की चोरी बंद करो'' के नारे लगाने लगे।

# संजय वात्सायन बने भारतीन नौसेना के 47वें उपप्रमुख, रणनीति और मिसाइल सिस्टम में हासिल है बादशाहत

नई दिल्ली। वाइस एडमिरल संजय वात्सायन ने एक अगस्त को नौसेना के 47वें उपप्रमुख के रूप में पदभार संभाल लिया। वह मिसाइल और गनरी सिस्टम के विशेषज्ञ हैं। इससे पहले वे कई अहम संचालन, स्टाफ और प्रशिक्षण पदों पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। भारतीय नौसेना ने यह जानकारी सोशल मीडिया पर दी। संजय वात्सायन ने एक जनवरी 1988 को नौसेना में कमीशन प्राप्त किया था। अपनी सेवा के दौरान उन्होंने डिप्टी चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ (डीसीआईडीएस), पूर्वी नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ, नेशनल डिफेंस अकादमी के डिप्टी कमांडेंट, पूर्वी बेड़े के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग और नौसेना मुख्यालय में पॉलिसी और प्लान्स के सहायक प्रमुख जैसे महत्वपूर्ण पदों पर काम किया है। वत्स्यायन ने वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामिनाथन का स्थान लिया है, जिन्होंने पश्चिमी नौसेना कमान (वेस्टर्न नेवल कमांड) के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ का पद संभाल लिया है। यह बदलाव 31 जुलाई को मुंबई में INS शिकरा में एक समारोह के दौरान हुआ। स्वामिनाथन ने गौरव स्तंभ पर शहीदों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की।

**नए DCIDS ने भी संभाला कार्यभार**

इसके साथ ही वाइस एडमिरल विनीत मैकार्टी ने एक और अहम पदभार संभाला है। उन्होंने इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ के डिप्टी चीफ (नीति योजना और बल विकास) के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। इससे पहले वे नेवल मुख्यालय में कंट्रोलर पर्सनल सर्विसेज के पद पर कार्यरत थे। उनकी नियुक्ति से तीनों सेनाओं के बीच तालमेल, रणनीतिक नीति निर्माण और भविष्य की सैन्य तैयारी को गति मिलेगी।